विकास लक्ष्यों को आगे ले जाने का समय

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने जो मेहनत की है, उसे आगे ले जाना होगा।

ब्यार्न लम्बोर्ग
निदेशक
कोपेनहेगन कन्सेंसस सेंटर

हालांकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 के लिए निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं किया है, मगर इस दौरान अनेक क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2011-12 तक भारत में गरीबों की संख्या घटकर आधी हो गई, जो इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। भारत ने सबको प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। 1990 तक पांच साल से कम आयु के लगभग 33 लाख भारतीय बच्चे किसी न किसी कारणवश मृत्यु का शिकार होते थे। इस वर्ष इस संख्या के घटकर 13 लाख हो जाने का अनुमान है। यानी भारत अब हर साल 20 लाख बच्चों को मृत्यु का शिकार बनने से बचा पा रहा है।

अब जब हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के स्थान पर 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो भारत के लिए एक मौका है कि वह और प्रभावी लक्ष्य तैयार करे। संयुक्त राष्ट्र ने 169 वैश्विक विकास लक्ष्यों की लंबी सूची तैयार की है। इनमें अति निर्धनता के उन्मूलन और भुखमरी की समाप्ति जैसे लक्ष्य भी हैं, तो सतत पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे भी। कोपेनहेगन कन्सेंसस सेंटर में 80 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने इन लक्ष्यों का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर हम इन लक्ष्यों पर एक रुपये का निवेश करते हैं, तो सात रुपये के सामाजिक लाभ हासिल कर सकेंगे। इनमें से 19 स्मार्ट लक्ष्यों पर खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये से 32 रुपये मूल्य के सामाजिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

ऐसे निवेश का एक उदाहरण कृषि अनुसंधान और विकास है। खाद्य सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत ने लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। 60 के दशक के अंत में, हरित क्रांति ने भारत की कायापलट की और उच्च पैदावार वाली फसलों, कीटनाशकों और खाद की बदौलत लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया, जबकि बाकी दुनिया में यह प्रगति नहीं दिखी। कोपेनहेगन कन्सेंसस सेंटर के अध्ययन से पता लगता है कि अगले 15 वर्षों में कृषि अनुसंधान और विकास पर अतिरिक्त 55 खरब भारतीय रुपये खर्च करने से हर साल पैदावार में 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि होगी। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं लगता, पर इससे 190 खरब रुपये का लाभ प्राप्त होगा और साढ़े सात करोड़ लोगों को भुखमरी से बचाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य के मामले में भारत व विश्व स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, मगर स्वास्थ्य प्रणाली के कमजोर होने और कई दवाओं के लिए प्रतिरोध पैदा होने से इस दिशा में अनेक बाधाएं हैं। भारत में टीबी का शिकार होने वालों की संख्या बहुत अधिक है, इसके बावजूद स्वास्थ्य खर्च का 25 प्रतिशत जहां एचआईवी में चला जाता है, वहीं टीबी के हिस्से केवल चार प्रतिशत आता है। इसलिए खास छोटे स्मार्ट लक्ष्यों की सूची बनाकर भारत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)